PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rajasthan Patrika, Jaipur
Tuesday 16th June 2015, Page: 11
Width: 12.38 cms, Height: 20.90 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.24.30

तीन साल में 100 प्रोसेसिंग यूनिट बंद

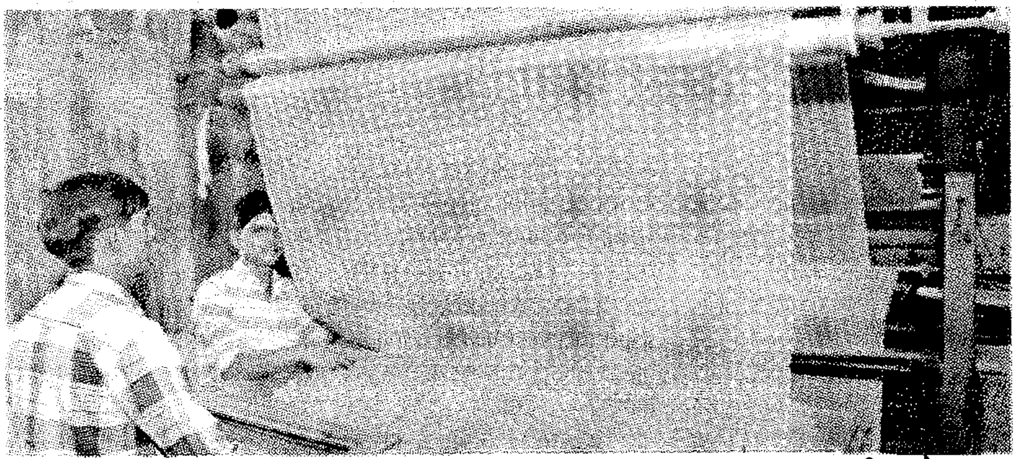

घटते लाभ और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से दूसरे कारोबार में उद्यमियों का रुझान बढ़ा

सूरत @ पत्रिका

patrika.com/city

कपड़ा उद्योग की मंदी से उद्यमी अन्य व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तीन साल पहले तक सूरत समेत दक्षिण गुजरात में 425 से अधिक डाइंग प्रोसेसिंग यूनिट थीं, लेकिन घटते लाभ, बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा समस्याओं के कारण प्रोसेसर्स यूनिट बंद कर रहे हैं। फिलहाल लगभग 325 यूनिट ही चालू हैं। इनमें से भी कई बंद होने की कगार पर हैं।

कपड़ा उद्योग के सूत्रों के अनुसार कभी सस्ते कपड़ों के लिए मशहूर सूरत का कपड़ा उद्योग इन दिनों मंदी के दौर से गुजर रहा है। कई दूसरे शहरों में मंडियां बनने के कारण व्यापारी बंट गए हैं। सूरत की सस्ती साड़ियों के सामने अब दूसरे शहरों की वर्क और महंगी साड़ियां प्रतिस्पर्धा में आ गई हैं। वहीं पॉलिएस्टर ड्रेस का अस्तित्व भी खतरे में है। कॉटन के कपड़ों की बढ़ती मांग के कारण सूरत के ड्रेस मटीरियल की बिक्री पचास फीसदी से भी ज्यादा घट गई है। ऐसे में वीवर्स और प्रोसेसर्स के सामने बड़ी चुनौती है।

प्रोसेसिंग यूनिट की राह में कई मुश्किलें हैं। सरकारी नियमों का पालन, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, जॉब वर्क का अभाव तथा घटते लाभ के कारण पिछले तीन-चार साल में सूरत समेत दक्षिण गुजरात में 100 से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो चुकी हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। यूनिट बंद करने के पीछे अन्य वैकल्पिक रास्तों से होने वाली आय भी एक कारण है। उद्यमियों का मानना है कि करोड़ों रुपए की पूंजी लगाकर और मेहनत करने के बाद भी कपड़ा उद्योग में लाभ का कोई ठिकाना नहीं है। इसकी अपेक्षा वह जमीन बेचकर ब्याज पर रुपए देने या अन्य व्यवसाय में निवेश करना मुनासिब मान रहे हैं।

रोजाना नई चुनौती

प्रोसेसिंग यूनिट बंद किए जाने का मुख्य कारण बदलते फैशन की मार तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। महिलाएं फैशनेबल कपड़ों की ओर बढ़ रही हैं। इससे कपड़ों की मांग कम हो गई है। प्रतिस्पर्धा ने उद्यमियों की कमर तोड़ दी है। सरकार के नियमों के कारण भी प्रोसेसर्स परेशान हैं। इसलिए वह सरदर्द पालने की बजाय नया व्यवसाय अपनाना पसंद कर रहे हैं।

कमल विजय तुलस्यान, प्रोसेसर

राह नहीं आसान

पांच साल पहले जितनी सरलता से व्यापार होता था, अब वैसा नहीं है। औद्योगिक गैस, कोयला, केमिकल, मजदूरी, यातायात खर्च, कच्चे माल की लगातार बढ़ती कीमतों के मुकाबले प्रोसेसर्स जॉब वर्क नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अन्य व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा है, इसलिए कई प्रोसेसर्स इस व्यवसाय से निकल रहे हैं।

जीतू वखारिया प्रमुख, साउथ गुजरात टैक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Economic Times , Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 3
Width: 8.60 cms, Height: 15.95 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.46.27

RELIEF PACKAGE

Centre to Give J&K Another ₹2,437 crore

Our Political Bureau

New Delhi: The Centre will release ₹2,437 crore to the Jammu & Kashmir government this year, taking the total relief package to the flood-ravaged state to more than ₹5,000 crore, besides working on a long-term development plan for the state, home minister Rajnath Singh and finance minister Arun Jaitley announced on Tuesday.

NITI Aayog CEO Sindhushree Khullar and secretary, expenditure, Ratan P Watal will visit J&K to develop a long-term vision for the development of the state, and their suggestions will be considered by the government in that respect, Jaitley said.

Holding a joint press conference with Singh to list out the package for J&K, where the BJP is in an uneasy alliance with PDP, Jaitley said the Centre had already released ₹2,602 crore for relief and rehabilitation after the devastating floods in the state last year.

"This year, ₹2,437 crore more will be released, taking the total aid to over ₹5,000 crore. The larger plan regarding development of infrastructure in power, highways, health, HRD, water resources, tourism, textile and education sectors will also be rolled out after suggestions from the NITI Aayog CEO and secretary, expenditure, who will be visiting J&K next week," the finance minister said.

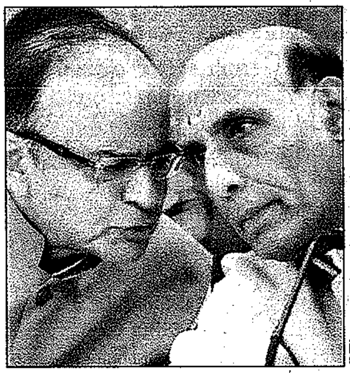

Rajnath Singh with Arun Jaitley at press conference in Delhi on Tuesday

Singh said the development of J&K was a "full-fledged" commitment of the Centre towards the state. "The existing allocation after the floods was not enough. Hence, more funds are now being allocated," the home minister said.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Line, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 17
Width: 18.58 cms, Height: 8.03 cms, a4r, Ref: pmin.2015-06-17.42.132

Coir exports up 10.5%; fetch ₹1,630 crore

V SAJEEV KUMAR
Kochi, June 16

Overseas demand for coir pith and coir fibre boosted country's coir and products exports in the 2014-15 fiscal, witnessing a 10.5 per cent growth in value and 16 per cent growth in quantity.

The exports clocked a revenue figure of whopping ₹1,630 crore during the period compared to ₹1,476 crore in the previous fiscal.

The country exported 6,26,666 tonnes against 5,37,040 tonnes in the preceding year.

China emerged as the major importer of coir fibre for manufacturing mattress boards and their focus to import more coir pith/grow bags to cater to horti/agricultural requirements have also contributed more to the export kitty, Surendra Nath Tripati, Chairman, Coir Board, said.

Value-added products

Coir fibre with export earnings of ₹419.23 crore constituted 26 per cent of the total products exports.

Similarly, coir pith with an export of ₹432.95 crore comprised 27 per cent.

All other value-added items put together constitute 47 per cent of the total exports, he said.

Dragon demand

Of the total 115 countries, the Chairman said that China topped the importing countries with 28.6 per cent in value and 39 per cent in quantity.

The US emerged as the second largest importer with a share of 21.3 per cent in value and 12.4 per cent in quantity.

According to board officials, coir handloom products exports also showed a marginal increase by quantity but no increase by value compared to last year. While coir pith, coir fibre, handloom mat, coir rope, curled coir and coir rugs and carpets registered a growth ranging from 12 to 45 per cent, the officials said that coir yarn, tufted mat, power-loom mat, handloom matting, coir geo-textiles and rubberised coir recorded a decline.

The Board's export market development assistance to popularise coir and products abroad also yielded results given the growth in exports both in quantity and value terms, the officials added.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Line, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 4
Width: 4.54 cms, Height: 8.90 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.42.40

'Removal of benefits in foreign trade policy to hit exports'

PRESS TRUST OF INDIA

Mumbai, June 16

Removal of benefits on exports to African countries in the new foreign trade policy will affect shipments of value-added products such as cotton dyed and printed fabrics, textile industry body said.

"The new Foreign Trade Policy 2015-20 has removed all benefits on exports to African countries. This has had a serious impact on exports of value added products like cotton dyed and printed fabrics and made-ups to African countries," Cotton Textiles Export Promotion Council (Texprocil) Chairman RK Dalmia said in a release issued here.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 12
Width: 9.95 cms, Height: 9.33 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.38.99

खादी की बिक्री में 60 फीसद की उछाल

खादी डेनिम प्रदर्शनी का उद्घाटन करते केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र। जागरण

नई दिल्ली, प्रेट्र : कम से कम एक खादी कपड़ा खरीदने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद खादी उत्पादों की बिक्री में 60 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र ने मंगलवार को यह दावा किया। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में खादी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाने की वकालत की थी। मंगलवार को यहां खादी डेनिम प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मिश्र ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए आंकड़ों में वृद्धि की बात कही। एमएसएमई मंत्री ने पूर्वोत्तर पीएमईजीपी प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विदेश में खादी की मांग तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा खादी की मैन्यूफैक्चरिंग पर ध्यान देने की जरूरत है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 14
Width: 4.06 cms, Height: 9.52 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.30.144

मोदी की अपील से खादी की बिक्री में 60 फीसदी उछाल

नई दिल्ली (प्रे)। कम से कम एक खादी कपड़ा खरीदने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद खादी उत्पादों की बिक्री में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र ने मंगलवार को यह दावा किया। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में खादी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाने की वकालत की थी। मंगलवार को यहां खादी डेनिम प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मिश्र ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए आंकड़ों में वृद्धि की बात कही। एमएसएमई मंत्री ने पूर्वोत्तर पीएमईजीपी प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विदेश में खादी की मांग तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा खादी की मैन्यूफैक्चरिंग पर ध्यान देने की जरूरत है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Millennium Post, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 12
Width: 12.51 cms, Height: 16.26 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.28.129

CCEA may raise MSP of paddy, other kharif crops today

NEW DELHI: The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) is likely to approve tomorrow a proposal to raise the minimum support price (MSP) of paddy by Rs 50 to Rs 1,410 per quintal for this year. "The CCEA meeting is scheduled for tomorrow. The proposal on MSP of kharif (summer) crops is listed on the agenda for discussion," Agriculture Secretary Siraj Hussain said.

The Agriculture Ministry has moved a CCEA note on MSP of various crops for the 2015-16 kharif season taking into account the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), a government advisory body.

According to sources, CACP has recommended a modest increase of Rs 50 per quintal to Rs 1,410 in the MSP for paddy farmers for the 2015-16 kharif season.

It has also suggested a hike of Rs 100 per quintal in the support price of ragi to Rs 1,650 and Rs 30 per quintal for groundnut MSP to Rs 4,030.

CACP has also recommended a higher MSP for pulses to boost domestic production and reduce country's dependence on imports. Sources said it is to be seen whether CCEA will approve the CACP's suggestions or take the political route to fulfill the BJP's 2014 poll promise of fixing MSP at 50 per cent profit margin over the cost of production. Usually, the government accepts CACP's recommendations on the crop pricing issue.

MSP is the rate at which government buys the grain from farmers. Paddy is the main crop grown in the kharif (summer) season. Sowing of kharif crops has already started with the onset of the South-West monsoon from June.

According to government data, area sown under the rice crop was higher at 4.71 lakh hectares till the last week of this season as against 4.52 lakh hectares in the same period last year. The sowing area under cotton, sugarcane and jute remained lower in the said period. Rice production is pegged at 102.54 million tonnes in the ongoing 2014-15 crop year (July-June) as against the record 106.65 million tonnes in the previous year. An increased MSP may encourage farmer for greater sowing of paddy. PTI

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Financial Chronicle, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 8
Width: 7.67 cms, Height: 2.66 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.29.66

Continue FTP benefits: trade body

Removal of benefits on exports to African countries in the new FTP will affect shipments of value added products like cotton dyed and printed fabrics, textile industry body said on Tuesday.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Millennium Post, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 5
Width: 8.84 cms, Height: 17.90 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.28.82

KVIC launches denim range to woo youth

PIC BY NAVEEN SHARMA

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: In a first of its kind the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) on Tuesday launched denim designer wear to attract youngsters towards the indigenous product.

Launching the new range, Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Kalraj Mishra said: "Khadi is becoming a global product now. Countries such as the UK, USA and Australia, among others, have shown a keen interest in setting up showrooms of khadi products. To meet the global demand, we have to make khadi clothes as per need and style."

KVIC CEO-cum commissioner AK Jha said: "We have taken a lead in introducing khadi denims as Arvind Mills, a denim cloth manufacturer for leading brands, has submitted a proposal for the same. Since khadi is our product, we will try to meet the domestic demand by producing quality denim products of khadi. We will not let it to go in private hands."

A Prime Minister's Employement Generation Programme (PMEGP) window was also inaugurated on the occasion. The programme aims to showcase products produced by micro entrepreneurs from all over the country. In the first phase, micro entrepreneurs from North East Region, along with khadi institutions, have displayed their products under the PMEGP window. North-east products such as cane, bamboo, munga silk and andi silk, among handicraft items, are also available in the exhibition.

Khadi Gramodyog Bhavan has also been awarded an ISO 9001:2008 certificate, which was awarded by TUV India. MSME secretary Madhav Lal was and other senior officials of the ministry were also present.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Punjab Kesari, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 9
Width: 8.10 cms, Height: 10.42 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.48.106

खादी की बिक्री 60 प्रतिशत बढ़ी : कलराज

नई दिल्ली, (भाषा): सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्री कलराज मिश्र ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद खादी उत्पादों की बिक्री में 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मोदी ने लोगों से खादी का कम से कम एक परिधान खरीदने की अपील की थी। एक आधिकारिक बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया है, ''प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो संबोधन 'मन की बात' में लोगों से खादी का कम से कम एक परिधान खरीदने को कहा था। उनकी इस अपील के बाद खादी की बिक्री 60 प्रतिशत बढ़ी है।'' मिश्र ने यहां खादी डेनिम प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने पूर्वोत्तर पीएमईजीपी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मिश्र ने न केवल बाजार आधारित बल्कि उत्पाद आधारित खादी के विनिर्माण पर जोर देते हुए कहा कि विदेशों में भी खादी की काफी मांग है।

सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित

मोगा च(पंजाब), (भाषा): भारत में मैगी के विनिर्माण में जुटे करीब 1,500 कर्मचारी इस इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड पर प्रतिबंध के बाद प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मैगी पर प्रतिबंध से आपूर्तिकर्ता भी प्रभावित हुए हैं। नेस्ले इंडिया की मसालों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता मोगा की पारस स्पाइसेस लि. ने पहले ही अपने 200 अस्थायी कर्मचारियों में से कुछ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। नेस्ले इंडिया ने हालांकि अभी तक अपने किसी स्थायी कर्मचारी को नहीं हटाया है।